Period	Retail Issue price (Rs. per Kg.)
1-1-89 to 24-7-91	5.25
24-7-91 to 20-1-92 (Evening)	6.10
21-1-92 to 16 2 93	6.90
17-2-93 to 31-1-94	8.30
1-2-94 to till date	9.05

Edible Oil: So far as imported RBD Palmolein is concerned, the average CIF price of imports in US S and the issue price fixed by the Government under PDS during the above period, as per information furnished by STC, re given below:-

Year	Average Price (CIF in US $ PMT)	Issue Price (Rs. / PMT) With effect from	PL (Bulky SP)	15 kg. Tin
1991-92	372.69	1-9-88	13150	14500
1992-93	441.59	26-1-91	16500	19000
1993-94	384.20	4-1-92	22000	25000
1994-95	561.20	21-1-94 to till date	24000	27000

The import of crude Soyabean oil was made under USAID & sold to vanaspati manufacturers/refiners.

Sugar

(c) The details of quantities of levy sugar lifted by the State Governments/UTs from Jan.-June and July-December during the years 1991 to 1994, are given in the Annexure. (*See* Appendix 173, (Annexure No. 67)

Edible Oil: As per information furnished by STC, the imported RBD Palmolein allocated to and lifted by the State Government /UTs under PD during each of the six months in January-June and Juuly-December from 1991 to 1994 is given at Annexure. (*See* Appendix 173, Annexure No. 68)

(d) As on 31st December, 1994, stocks of 40.89 lakh tonnes of foodgrain had been kept in open by FCI. (This does not include paddy stocks stored in the Rice Mills yards for milling into rice specially in Punjab).

Recommendations of the working Group in Ministry

*292. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY :

SHRI CHIMANBHAI MEHTA :

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND

PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a working group set up by the Ministry of recommended setting up of a Public Utilities Commission to oversee the operation of various public utilities from the viewpoint of their meeting the legitimate demand and requirement of their services; and

(b) if so, what is the final outcome and what are the other recommendations of the group?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) and (b). Yes, Sir, Public Utilities Commission is a new concept for our country and the various ramifications of the proposal have to be considered in depth before arriving at a decision

बंधुआ बाल मजदूर

***293. श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**

श्री अनन्तराम जायसवाल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश भर में बंधुआ बाल मजदूरों की सर्वाधिक संख्या किन-किन राज्यों में है और उनसे अधिकांश किन-किन उद्योगों में कार्यरत हैं और ऐसे बंधुआ बाल मजदूरों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा बंधुआ बाल, मजदूरों को मुक्त करा कर उनके पुनर्वास के लिए अब तक कोई व्यवस्था की गई है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में विभिन्न उद्योगों में कार्यरत बंधुआ बाल मजदूरों को मुक्त कराने तथा उनके पुनर्वास कल्याण के लिए कोई समयावधि निश्चित की गई है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार क्या त्वरित कार्रवाई करने पर विचार कर रही है ?

श्रम मंत्री (श्री पी० एन० संगमा) (क) से (ग) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथा सूचित विभिन्न राज्यों में अभिज्ञात और पुनर्वासित बंधित बाल श्रमिकों की संख्या निम्नानुसार है :

राज्य का नाम	अभिज्ञात तथा पुनर्वास बंधित बाल श्रमिकों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	118
2. बिहार	388
3. उत्तर प्रदेश	341
4. कर्नाटक	75
5. मध्य प्रदेश	545
6. महाराष्ट्र	5
7. हरियाणा	45
8. दिल्ली	7

प्रत्येक राज्य के उन उद्योगों के नाम जिनमें ये बालक बंधुआ हालत में कार्य कर रहे थे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि उत्तर प्रदेश राज्य से सूचित बंधुआ बाल श्रमिक कालीन उद्योग में नियोजित थे और दिल्ली में उन्हें निर्माण कामगार के रूप में कार्य करते पाया गया। बालकों को मुक्त करवा दिया गया है। और उनके मात-पिता को सौंप दिया गया है।

ऐसे बंधुआ बाल श्रमिकों को उसके पहचान करने के साथ ही बंधुआ हालत से मुक्त करवा दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार की एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके अन्तर्गत पहचान किए गए बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास जिनमें बाल बंधुआ श्रमिक भी शामिल हैं, हेतु राज्य सरकारों